दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 | Postal Registration No-055/Raigarh DN CG | रायगढ़, शुक्रवार 23 फरवरी 2024 | पृष्ठ-4, मूल्य 3 रुपए | वर्ष-06, अंक- 147

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

महत्वपूर्ण एवं खास

गुलमर्ग में एवलांच का कहर, एक टूरिस्ट की मौत, कई फंसे

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में वीरवार को भयंकर हिमस्खलन हुआ। इस हिमस्खलन में एक टूरिस्ट की मौत हो गई है, जबकि एक घायल हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक स्थानीय व्यक्ति और कुछ विदेशी लापता हैं, कुछ फंसे हुए हैं, जिनका हेलिकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक 5 लोगों को बचाया गया है। इन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। अफरवाट चोटी से लगे खिलान मार्ग पर गुरुवार (22 फरवरी) दोपहर 2 बजे यह बर्फीला तूफान आया। अधिकारियों ने बताया कि आज गुलमर्ग के ऊपरी हिस्से में कोंगदूरी ढलान के पास भारी हिमस्खलन हुआ। न्यूज एजेंसी ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि विदेशी लोग स्थानीय लोगों के बिना स्की ढलानों पर गए थे। सेना के जवान और जम्मू-कश्मीर प्रशासन की एक पेट्रोलिंग टीम बचाव-सह-खोज अभियान चला रही है। बता दें कि गुलमर्ग में, जहां जनवरी के पहले कुछ हफ्तों में बर्फ का नामों-निशान नहीं था, फरवरी की शुरुआत से भारी बर्फबारी देखी जा रही है।

25 मई को खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट

देहरादून (आरएनएस)। उत्तराखंड में मई के महीने से चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है। उत्तराखंड में स्थित सिक्खों के पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहिब के भी कपाट खुलने और बंद होने की तारीख की घोषणा हो गई है। हेमकुंड साहिब के कपाट इस बार 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे और 10 अक्टूबर को बंद हो जाएंगे। कपाट खुलने के साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा आरंभ हो जाएगी। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने गुरुवार को उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कपाट खुलने और बंद होने की जानकारी दी। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति दे दी है। मुख्य सचिव ने कहा कि यात्रा के सुचारू संचालन के लिए प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग किया जाएगा।

चीन में मालवाहक जहाज के पुल से टकराने से दो की मौत, तीन लापता

बीजिंग। चीन के गुआंग्डोंग प्रांत के गुआंगझोउ में गुरुवार सुबह एक मालवाहक जहाज के पुल से टकराने के कारण ढांचे का एक हिस्सा ढह गया। इससे दो लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य लापता हो गए। यह घटना सुबह करीब 5.30 बजे तब हुई, जब एक कंटेनर जहाज लिक्सिंशा ब्रिज के घाट से टकरा गया। इससे पांच वाहन डूब गए। प्रारंभिक जांच के अनुसार, पांच वाहनों में से दो नदी में और अन्य जहाज पर गिर गए। दुर्घटना में चालक दल का एक सदस्य मामूली रूप से घायल हो गया। बचाव प्रयास जारी हैं और दुर्घटना के कारण की जांच की जा रही है।

गाजा के नुसीरत शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 17 लोगों की मौत

गाजा। मध्य गाजा पट्टी में नुसीरत शरणार्थी शिविर में एक घर पर हुए इजरायली हवाई हमले में कम से कम 17 फिलिस्तीनी मारे गए और 34 से अधिक घायल हो गए। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी हैं और हताहतों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। सूत्रों ने कहा कि पीड़ितों को अल-बलाह शहर के अल-अक्सा शहीद अस्पताल में भर्ती किया गया है। एक इजरायली युद्धक विमान ने कई विस्थापित परिवारों को शरण देने वाले घर पर कई मिसाइलों से हमला किया। बड़े पैमाने पर हुए विस्फोट ने इमारत गिरा दिया और शिविर के पश्चिमी हिस्से में घरों को बहुत नुकसान पहुंचाया।

मेक्सिको में अपराधिक गिरोहों के बीच झड़प, 12 लोगों की मौत

मेक्सिको सिटी ,22 फरवरी। मेक्सिको के दक्षिणी राज्य ग्युरेरो में प्रतिद्वंद्वी आपराधिक गिरोहों के बीच झड़प में कम से कम 12 लोग मारे गए। यह जानकारी राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर ने बुधवार को दी। ओब्रेडोर ने मेक्सिको सिटी के नेशनल पैलेस में एक दैनिक संवाददाता सम्मेलन में संवाददाताओं से कहा कि घटना की जांच चल रही है और नेशनल गार्ड के सैनिक पहले से ही घटनास्थल पर मौजूद हैं।

भारतीय नौसेना की बढ़ेगी ताकत : ब्रह्मोस मिसाइल खरीद के लिए 19 हजार करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी मिली

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय नौसेना की ताकत में और इजाफा होने जा रहा है। नौसोना को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने युद्धपोतों पर तैनाती के लिए 200 से अधिक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने एएनआई को बताया कि बुधवार शाम को हुई बैठक में लगभग 19,000 करोड़ रुपये के सौदे को मंजूरी दी गई। ब्रह्मोस एयरोस्पेस और रक्षा मंत्रालय के बीच मार्च के पहले सप्ताह में अनुबंध पर हस्ताक्षर होने की तैयारी है।

ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए जहाज-रोधी और हमले के संचालन के लिए मुख्य हथियार है, जो नियमित रूप से हथियार प्रणाली से फायर करते हैं। ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है, जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।

ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का बड़े पैमाने पर स्वदेशीकरण किया गया है और इसके ज्यादातर पार्ट्स का का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को जल्द ही फिलीपींस को भी निर्यात करने की तैयारी है, जो इसका पहला वैश्विक ग्राहक है। बता दें कि कई देश ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के कई देशों ने कई तरीकों से तैनाती के लिए इस मिसाइल प्रणाली में गंभीर रुचि दिखाई है।

ब्रह्मोस युद्धपोतों के लिए मुख्य हथियार- ब्रह्मोस भारतीय नौसेना के युद्धपोतों के लिए जहाज-रोधी और हमले के संचालन के लिए मुख्य हथियार है, जो नियमित रूप से हथियार प्रणाली से फायर करते हैं।

ब्रह्मोस एयरोस्पेस भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है, जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों या भूमि प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है।

फिलीपींस को भी निर्यात करने की तैयारी- ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल का बड़े पैमाने पर स्वदेशीकरण किया गया है और इसके ज्यादातर पार्ट्स का का स्वदेशीकरण किया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल को जल्द ही फिलीपींस को भी निर्यात करने की तैयारी है, जो इसका पहला वैश्विक ग्राहक है।

कई देश मिसाइल खरीदने में दिखा रहे रुचि- बता दें कि कई देश ब्रह्मोस मिसाइल में रुचि दिखा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के कई देशों ने कई तरीकों से तैनाती के लिए इस मिसाइल प्रणाली में गंभीर रुचि दिखाई है।

अतुल राणे की अध्यक्षता में ब्रह्मोस एयरोस्पेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित 5 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी काम कर रहा है। ब्रह्मोस के चेयरमैन ने कहा था कि फिलीपींस के साथ 375 मिलियन डॉलर के पहले निर्यात सौदे के बाद, उनकी टीम 2025 तक 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य रख रही है।

भारतीय सेना की बहादुरी ने मौत के मुंह में फंसे 500 लोगों को बचाया

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारतीय सेना के जवान कठिन परिस्थितियों में भी ड्यूटी देकर देश की अमन-शांति को बहाल करते हैं। इसके अलावा देश को दुश्मनों से बचाना हो या देशवासियों को परेशानियों से निकालना हो, सेना हमेशा सबसे आगे खड़ी नजर आती है। इसी कड़ी में सेना के बहादुर जवानों ने जान की बाजी लगाकर बर्फ में फंसे 500 लोगों को सुरक्षित निकासा।

जानकारी के अनुसार सिक्किम में भारत-चीन सीमा पर नाथुला में भारी बर्फबारी में 500 से अधिक पर्यटक फंस गए, जिन्हें भारतीय सेना के जवानों ने सुरक्षित बाहर निकाला। सेना ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी।

सेना ने बताया कि त्रिशक्ति कोर के जवानों को बचाव के लिए वहां भेजा गया और उन्होंने फंसे हुए पर्यटकों को मदद प्रदान की। बयान में कहा है कि पर्यटकों को गर्म भोजन और त्वरित चिकित्सा प्रदान की गई और उन्हें सुरक्षित परिवहन उपलब्ध कराया गया। त्रिशक्ति कोर ने इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा की हैं।

कैबिनेट ने महिला सुरक्षा पर अम्ब्रेला योजना जारी रखने के प्रस्ताव को दी मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकार ने 'महिला सुरक्षा' पर अम्ब्रेला योजना को 2025-26 तक जारी रखने का फैसला किया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया।

आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के दौरान 1179.72 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 'महिलाओं की सुरक्षा' पर अंब्रेला योजना का कार्यान्वयन जारी रखने के गृह मंत्रालय (एमएचए) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

1179.72 करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय में से 885.49 करोड़ रुपये गृह मंत्रालय द्वारा अपने बजट से प्रदान किए जाएंगे, जबकि शेष 294.23 करोड़ रुपये निर्भया फंड से वित्त पोषित किए जाएंगे।

महिला सुरक्षा के लिए व्यापक योजना के तहत परियोजनाएं 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) 2.0 हैं, केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं का उन्नयन; राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं (एफएसएल) में डीएनए विश्लेषण, साइबर फोरेंसिक क्षमताओं को मजबूत करना; महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध की रोकथाम; महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने के लिए जांचकर्ताओं और अभियोजकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के साथ महिला सहायता डेस्क और मानव तस्करी-रोधी इकाइयां।

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के 30 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी, किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केस में एक्शन

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने गुरुवार सुबह पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के दिल्ली स्थित आवास और दफ्तर की तलाशी ली। इसके अलावा केंद्रीय एजेंसी ने जम्मू-कश्मीर में भी 30 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह मामला किश्तवाड़ में चिनाब नदी पर प्रस्तावित किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 2019 में 2200 करोड़ रुपये के सिविल वर्क का कॉन्ट्रैक्ट देने में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है।

बता दें कि सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि उन्हें राज्य का गवर्नर रहते परियोजना से संबंधित दो फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी। बता दें कि वह 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पिछले महीने भी इस केस में चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में लगभग 8 स्थानों पर छापा मारा था।

सीबीआई ने पिछले महीने अपनी रेड में 21 लाख रुपये (लगभग) से अधिक की नकदी के अलावा डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर, संपत्ति दस्तावेज बरामद किए थे। केंद्रीय एजेंसी ने चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (प्राइवेट) लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी, पूर्व अधिकारियों एमएस बाबू, एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया था। चौधरी 1994-बैच के जम्मू-कश्मीर-कैडर (अब एजीएमयूटी कैडर) के आईएएस अधिकारी हैं। यह आरोप है कि किरू जलविद्युत परियोजना से संबंधित सिविल कार्यों के आवंटन में, ई-टेंडरिंग के संबंध में दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया। यह भी आरोप लगाया गया कि सीवीपीपीपीएल की 47वीं बोर्ड बैठक में निर्णय लिया गया था कि रिवर्स नीलामी के साथ ई-टेंडरिंग के माध्यम फिर से क्रॉन्ट्रैक्ट आवंटित किया जाएगा। लेकिन चल रही निविदा प्रक्रिया को रद्द करने के बाद, इसे लागू नहीं किया गया और सीवीपीपीपीएल की 48वीं बोर्ड बैठक में पिछली मीटिंग के निर्णय को उलट दिया गया।

गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 पीएसीएस की आधारशिला भी रखेंगे प्रधानमंत्री

❐ **प्रधानमंत्री देश भर में 18,000 पीएसीएस में कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना का करेंगे उद्घाटन**

नई दिल्ली । देश के सहकारी क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी 24 फरवरी, 2024 को सुबह 10:30 बजे भारत मंडपम, नई दिल्ली में सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।

प्रधानमंत्री 'सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना' की पायलट परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस) में संचालित किया जा रहा है।

इस पहल के तहत प्रधानमंत्री गोदामों और कृषि से जुड़ी अन्य बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 पीएसीएस की आधारशिला भी रखेंगे। इस पहल का उद्देश्य पीएसीएस गोदामों को खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत करना, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना तथा नाबार्ड द्वारा समर्थित और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के नेतृत्व में सहयोगात्मक प्रयास के साथ देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल को कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) आदि जैसी विभिन्न मौजूदा योजनाओं के सम्मिलन के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है ताकि परियोजना में भाग लेने वाली पीएसीएस को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सब्सिडी और ब्याज अनुदान लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।

प्रधानमंत्री देश भर में 18,000 पीएसीएस में कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जो सरकार के "सहकार से समृद्धि" विजन के अनुरूप है। इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को फिर से नई ऊर्जा प्रदान करना तथा छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाना है।

इस महत्वपूर्ण परियोजना को 2,500 करोड़ रुपये से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है। इस पहल में निर्बाध एकीकरण और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए सभी कार्यात्मक पीएसीएस को एकीकृत एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में परिवर्तित किया जाना शामिल है।इस परियोजना का उद्देश्य इन पीएसीएस को राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़कर, उनकी संचालन दक्षता और शासन को बढ़ाना है, इस तरह करोड़ों छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। नाबार्ड ने इस परियोजना के लिए राष्ट्रीय स्तर का कॉमन सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो देश भर में पीएसीएस की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। ईआरपी सॉफ्टवेयर पर 18,000 पीएसीएस की ऑनबोर्डिंग पूरी हो चुकी है, जो परियोजना के कार्यान्वयन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

दर्दनाक हादसा : सोने की खदान ढहने से 15 लोगों की मौत- दर्जनों घायल

करोकस (आरएनएस)। वेनेजुएला के दक्षिणपूर्वी बोलिवर राज्य के अंगोस्टुरा शहर के ला परागुआ में एक खदान ढहने से 15 लोगों की मौत हो गई जबकि 11 अन्य लोग घायल हो गए। यह जानकारी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रात को दी।

राष्ट्रपति ने कहा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद फंसे खनिकों का पता लगाने के लिए खोज एवं बचाव दल को इलाके में तैनात किया जा रहा है। मादुरो ने राज्य टेलीविजन पर कहा, हमने बोलिवर राज्य के गवर्नर एंजेल मार्कानो के साथ मिलकर सभी नागरिक सुरक्षा टीमों को तुरंत भेज दिया है और हम खोज एवं बचाव को मजबूत करेंगे।

मादुरो ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ड्रिलिंग के कारण खदान ढहा है और 30 मीटर की गहराई तक ढह गया।

लोकसभा चुनाव : निर्वाचन आयोग ने बंगाल में संवेदनशील बूथों की सूची मांगी

कोलकाता (आरएनएस)। भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पश्चिम बंगाल में संवेदनशील बूथों की सूची अविलंब मांगी है। राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा कि चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले ही सूची की मांग करना एक स्पष्ट संकेत है कि चुनाव से बहुत पहले राज्य के विभिन्न हिस्सों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के सूत्रों के कहा कि आयोग ने उन बूथों का विवरण भी मांगा है जिन्हें 2019 के लोकसभा चुनावों और 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में संवेदनशील घोषित किया गया था। यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव तैयारियों के संबंध में स्थिति का जायजा लेने के लिए ईसीआई की पूर्ण पीठ मार्च के पहले सप्ताह में पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। नवीनतम कार्यक्रम के अनुसार, पूर्ण पीठ 4 मार्च को आएगी और अगले दिन उनके प्रतिनिधि राज्य के शीर्ष नौकरशाहों तथा पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर कहा, संभवत:, पूर्ण पीठ संवेदनशील बूथों के विवरण के साथ चुनाव तैयारियों पर राज्य की प्रशासनिक मशीनरी के साथ चर्चा शुरू करना चाहती है, और आयोग ने तुरंत इस संबंध में सूची मांगी है। हाल ही में दो ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिनसे यह स्पष्ट है कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल ईसीआई की विशेष निगरानी में है। सबसे पहले, आयोग ने लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र बलों की 920 कंपनियों की तैनाती की मांग की है, जो किसी भी दूसरे राज्य से अधिक है। दूसरे, आयोग ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए नोडल अधिकारी के लिए राज्य सरकार की पहली पसंद को खारिज कर दिया है।

कैबिनेट ने ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के विस्तार को दी मंजूरी

नई दिल्ली ,22 फरवरी (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को ग्रामीण आबादी तक लाभ पहुंचाने के लिए अतिरिक्त गतिविधियों को शामिल करके राष्ट्रीय पशुधन मिशन में और संशोधन को मंजूरी दे दी।

योजना में नई गतिविधियों में व्यक्तियों, एफपीओ, एसएचजी, जेएलजी, एफसीओ और धारा 8 कंपनियों को प्रदान की जाने वाली 50 लाख रुपये तक की 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी के साथ घोड़े, गधे, खच्चर, ऊंट के लिए उद्यमिता की स्थापना शामिल है। साथ ही घोड़े, गधे और ऊंट के नस्ल संरक्षण के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी जाएगी। केंद्र सरकार घोड़े, गधे और ऊंट के लिए वीर्य स्टेशन और न्यूक्लियस प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपये देगी।

यह राशि निजी कंपनियों, स्टार्टअप/एसएचजी/एफपीओ/एफसीओ/जेएलजी/किसान सहकारी समितियों (एफसीओ) को 50 लाख रुपये तक 50 प्रतिशत पूंजी सब्सिडी के साथ चारा बीज प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई/चारा भंडारण गोदाम) के लिए उद्यमियों की स्थापना, धारा 8 कंपनियां, ग्रेडिंग संयंत्रों के साथ-साथ बीज भंडारण गोदामों सहित भवन निर्माण, रिसीविंग शेड, सुखाने का प्लेटफार्म और मशीनरी जैसे बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए है।

परियोजना की शेष लागत की व्यवस्था लाभार्थी द्वारा बैंक वित्त या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से की जानी चाहिए। चारा खेती के क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को गैर-वन भूमि, बंजर भूमि/रेंज भूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि के साथ-साथ वन भूमि में चारे की खेती और वन भूमि के साथ-साथ वनों से चारा उत्पादन के लिए सहायता दी जाएगी। इससे देश में चारे की उपलब्धता बढ़ेगी।

पशुधन बीमा कार्यक्रम को भी सरल बनाया गया है। किसानों के लिए प्रीमियम में लाभार्थी का हिस्सा कम कर दिया गया है और यह 15 प्रतिशत होगा, जबकि मौजूदा लाभार्थी हिस्सा 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत और 50 प्रतिशत है। प्रीमियम की शेष राशि केंद्र और राज्य द्वारा सभी राज्यों के लिए 60.40 के अनुपात में साझा की जाएगी। बीमा किए जाने वाले पशुओं की संख्या भी भेड़ और बकरी के लिए 5 मवेशी इकाई के बजाय 10 मवेशी इकाई तक बढ़ा दी गई है। इससे पशुपालकों को न्यूनतम राशि चुकाकर अपने पशुओं का बीमा